

शर्तों और छंटनी के डर से नजीकरण का वरिध करते हैं।

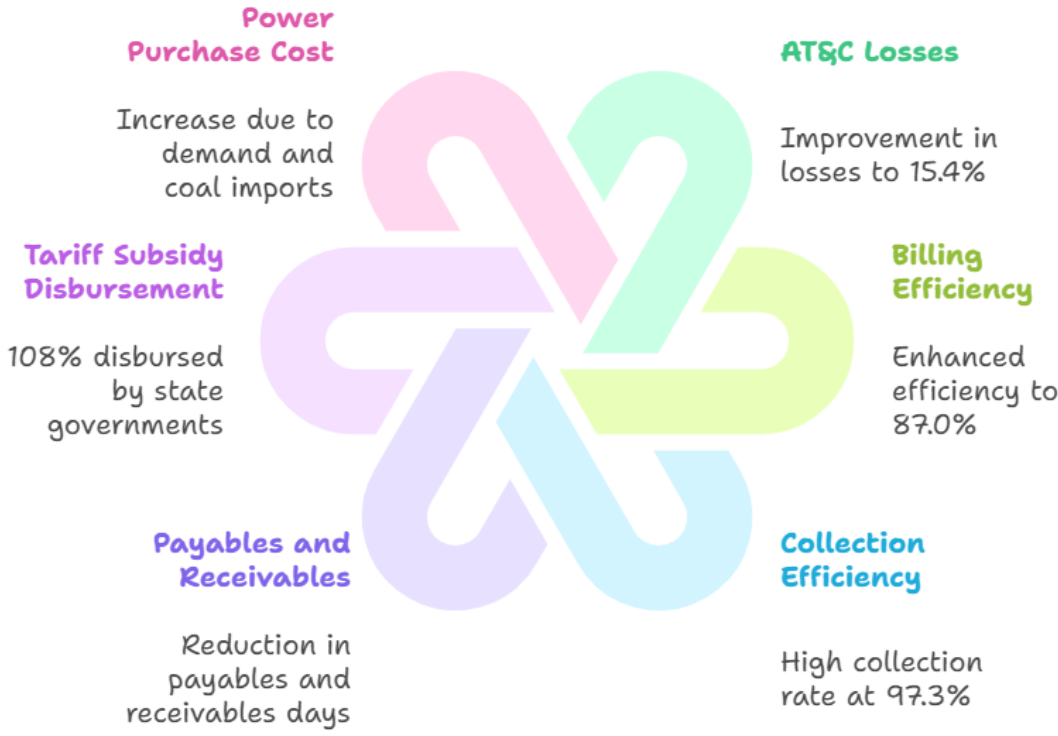
- दिल्ली की स्वैच्छक सेवानिवृत्त योजना जैसे अनुभव नौकरी की सुरक्षा और वित्तीय स्थितिको लेकर कर्मचारियों की चिंताओं को उजागर करते हैं।
- **जटिल वधिक और वनियामक परविशः वदियुत अधनियम, 2003** के अनुपालन, पूरण नजीकरण पर अनश्चितता और अस्पष्ट सुधार वकिलों के कारण चुनौतियाँ उत्पन्न होती हैं।
 - उदाहरण के लिये, चंडीगढ़ में **वधिक चुनौतियों** के कारण यह चिंता उत्पन्न हुई कि क्या नजी बोलीदाता ने सभी वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्तिकी, जिसके कारण प्रक्रिया में देरी हुई।
- **उपभोक्ताओं के लिये टैरफि संबंधी चिंताएँ: नजीकरण के बाद**, परचालन लागत और बुनियादी ढाँचे में नविश को कवर करने के लिये प्रायः **टैरफि** बढ़ाना आवश्यक हो जाएगा, जिससे उपभोक्ताओं के वरिध की संभावना बढ़ जाती है।
 - लागत वसूली की आवश्यकता और **सामर्थ्य के बीच संतुलन स्थापति करना** नयामकों और नजी क्षेत्र के लिये एक गंभीर चुनौती है।
- **संक्रमणकालीन समर्थन का अभावः 1990** के दशक में ओडिशा की नजीकरण वफिलता एक उदाहरण है, जहाँ पर्याप्त **वित्तीय और परचालन संक्रमणकालीन समर्थन के अभाव** के कारण वांछित परिणाम प्राप्त नहीं हुए।
 - ओडिशा के वपिरीत, दिल्ली की सफलता का श्रेय **3,450 करोड़ रुपए की संक्रमणकालीन नधि** को दिया जा सकता है, जिससे DISCOM को प्रारंभिक परचालन संबंधी बाधाओं का प्रबंधन करने में सहायता मिली।

राज्य DISCOM की सहायता हेतु सरकार की क्या कारयनीत है?

■ योजनाएँ:

- **उज्ज्वल DISCOM एशयोरेंस योजना (UDAY):** वित्तीय रूप से संकटग्रस्त DISCOM को संरक्षण प्रदान करने के लिये वर्ष 2015 में शुरू की गई UDAY योजना से राज्यों को कम ब्याज वाले बॉन्ड के रूप में 75% देनदारियाँ लेने की अनुमति प्रदान कर उनके ऋण में कमी आई है।
 - इसका लक्ष्य स्मार्ट मीटरिंग और चोरी में कमी जैसे उपायों के माध्यम से AT&C घाटे और बलिगि दक्षता में सुधार करना था।
 - **संशोधित वतिरण क्षेत्र योजना (RDSS):** 5 वर्ष की अवधि (वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26) के लिये 3,03,758 करोड़ रुपए के बजट के साथ प्रस्तुत की गई।
 - इस योजना का उद्देश्य समग्र देश में AT&C घाटे में 12 से 15% की कमी लाना और 2024-25 तक ACS और ARR के बीच के अंतर को खत्म करना है।
 - **एकीकृत वदियुत विकास योजना (IPDS):** शहरी वदियुत वतिरण अवसंरचना को मज़बूत करने के लिये शुरू की गई इस योजना का लक्ष्य विश्वसनीयता में सुधार, तकनीकी घाटे को कम करना और शहरी क्षेत्रों में बेहतर ग्राहक सेवा सुनिश्चित करना है।
- ### ■ अन्य उपायः
- **एकीकृत रेटिंगः DISCOM की एकीकृत रेटिंग**, जो प्रतविरष आयोजति की जाती है, से परचालन और वित्तीय मापदंडों का मूल्यांकन किया जाता है, जिससे अकुशलताओं की पहचान करने और जवाबदेही को प्रोत्साहित करने में मदद मिलती है।
 - DISCOM की एकीकृत रेटिंग के 12वें संस्करण में AT&C घाटे में कमी और बेहतर भुगतान चक्र जैसे सुधारों पर प्रकाश डाला गया।

Key Insights from Discoms Rating



- **वित्तीय सहायता और सब्सिडी:** वित्त वर्ष 2023 के दौरान, राज्य सरकारों ने बुक की गई टैरिफ सब्सिडी का 108% वितरित किया, जिससे DISCOM द्वारा घाटे की स्थिति में भी परचालन जारी रखना सुनिश्चित किया गया।
 - दिल्ली जैसे मामलों में, नज्दीकरण के बाद परचालन को स्थिर करने में 3,450 करोड़ रुपए का संक्रमणकालीन वित्तपोषण सहायक रहा।
- **नियामक सुधार: वलिंबति भुगतान अधिभार नियमों** के अंतर्गत देय दिनों की संख्या घटाकर 126 दिन और प्राप्य दिनों की संख्या घटाकर 119 दिन कर दिया है, जिससे DISCOM पर चलनधि संबंधी दबाव कम हो गया है।
 - ये नियम उत्पादन एवं पारेषण कंपनियों को समय पर भुगतान के लिये प्रोत्साहित करते हैं।
- **केंद्र शासित प्रदेशों (UT) में नज्दीकरण:** केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेशों की DISCOM के नज्दीकरण की पहल की, जिसमें दादरा और नागर हवेली और दमन और दीव 2022 में पहले राज्य रहे।
 - चंडीगढ़ और पुद्दुचेरी में हुई प्रगति, प्रतर्निध और मुकदमों के बावजूद जारी प्रयासों को दर्शाती है।

आगे की राह

- **सहयोगात्मक हतिधारक सहभागिता:** सरकारों को चिंताओं का समाधान करने और आम सहमत बनाने के लिये कर्मचारियों, उपभोक्ताओं और राजनीतिक समूहों को शामिल करना चाहिये, ताकि सुचारु परिवर्तन सुनिश्चित हो सके।
 - पेंशन देयता साझाकरण जैसे सुरक्षा उपायों के बारे में स्पष्ट संचार से प्रतर्निध को कम किया जा सकता है।
- **नियामक सुदृढीकरण:** राज्य विद्युत नियामक आयोगों को पारदर्शी टैरिफ निर्धारण लागू करने, दक्षता को प्रोत्साहित करने और उपभोक्ता हितों की रक्षा करने के लिये सशक्त बनाया जाना चाहिये।
- **कर्मिक टैरिफ युक्तिकरण:** टैरिफ समायोजन की वधि चरणबद्ध होनी चाहिये तथा लागत वसूली सुनिश्चित करते हुए सुभेद्य उपभोक्ताओं का सामर्थ्य बनाए रखने के लिये के लिये सब्सिडी प्रदान की जानी चाहिये।
- **बुनियादी ढाँचे का उन्नयन:** सेवा वितरण में सुधार और घाटे को कम करने के लिये ग्रिडों का आधुनिकीकरण, स्मार्ट मीटरिंग शुरू करना और प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने को प्राथमिकता दी जानी चाहिये।
- **चरणबद्ध वधि से खुदरा प्रतर्निध को प्रोत्साहित करना:** यद्यपि पूर्ण नज्दीकरण प्रभावी है, लेकिन चरणबद्ध तरीके से खुदरा प्रतर्निध की संभावना खोजने से उपभोक्ताओं को विकल्प मिला सकता है और समय के साथ सेवा की गुणवत्ता में सुधार हो सकता है।
- **सर्वोत्तम प्रथाओं से सीख लेना: सफल (दिल्ली) और असफल (ओडिशा)** दोनों मॉडलों से सीख लेकर सर्वोत्तम प्रथाओं का क्रियान्वन करने से नज्दीकरण के लिये प्रभावी नीतियाँ और रूपरेखा तैयार करने में मदद मिल सकती है।

दृष्टिभेनस प्रश्न:

प्रश्न. भारत में DISCOM के नजीकरण को आवश्यक बनाने वाले प्रमुख कारक और चुनौतियाँ क्या हैं और प्रणालीगत सुधार से कसि प्रकार इनका समाधान कया जा सकता है?

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

??????????:

प्रश्न. नमिनलखिति में से कौन-सा सरकार की एक योजना 'उदय'(UDAY) का उद्देश्य है? (2016)

- (a) ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों के कषेत्र में स्टार्टअप उद्यमियों को तकनीकी और वतितीय सहायता प्रदान करना ।
- (b) वर्ष 2018 तक देश के हर घर में वदियुत पहुँचाना ।
- (c) कोयला आधारति वदियुत संयंत्रों को समय के साथ प्राकृतकि गैस, परमाणु, सौर, पवन और ज्वारीय वदियुत संयंत्रों से बदलना ।
- (d) वदियुत वतिरण कंपनियों के बदलाव और पुनरुदधार के लयि वति्त प्रदान करना ।

उत्तर: (d)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/privatisation-of-power-discoms>

